

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

✓ 1. अपील संख्या – 1976/2014/उदयपुर.

2. अपील संख्या – 1977/2014/उदयपुर.

3. अपील संख्या – 1978/2014/उदयपुर.

मैसर्स युनाईटेड इंजीनियर्स, पनेरियों की मादड़ी, उदयपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर. ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

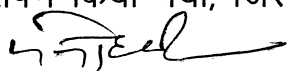
निर्णय दिनांक : 18/12/2014

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये तीन अपीलें उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'प्रशासनिक अधिकारी' कहा जायेगा) के प्रार्थना-पत्र संख्या प.15(8)कर/उपा.प्र./प्रशमन/उदय/05/1692 में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 17.9.2014 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. इन तीनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से तीनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-षष्टम, वृत्त-ब', उदयपुर द्वारा अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 20.06.2014 को किये जाने पर व्यवसाय स्थल पर 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल की बिक्री को करमुक्त जॉब चार्ज अकाउण्ट में दर्शाया जाना पाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कर चोरी किया जाना प्रमाणित पाये जाने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-ब', उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2011-12; 2012-13 व 2013-14 के वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.07.2014 को पारित करते हुए 5 प्रतिशत की दर से कर, धारा 61 के तहत शास्ति एवं देय कर विलम्ब से जमा कराने हेतु तदनुसार ब्याज का आरोपण किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-



लगातार.....2

अपील संख्या	अवधि	विवादित बिक्री	आरोपित कर	ब्याज	शास्ति	योग
1976 / 14	2011-12	54,50,000	2,72,500	92,650	5,45,000	9,10,150
1977 / 14	2012-13	18,68,000	93,400	20,548	1,86,800	3,00,748
1978 / 14	2013-14	56,04,000	2,80,200	33,624	5,60,400	8,74,224

4. उक्त आदेशों की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि की सीमा तक प्रकरणों को प्रशमन कराने हेतु प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 68(1) के तहत पृथक-पृथक प्रार्थना-पत्र दिनांक 04.08.2014 को प्रस्तुत किये गये। प्रशासनिक अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को उचित मानते हुए, पृथक-पृथक पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.09.2014 से अपीलार्थी के प्रशमन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिये। प्रशासनिक अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

6. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने प्रशासनिक अधिकारी के आदेशों को विधिविरुद्ध बताया एवं कथन किया कि प्रशासनिक अधिकारी ने प्रशमन आवेदन अस्वीकार करने से पूर्व अपीलार्थी को धारा 48 अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी के आदेश न्यायोचित नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के अपील संख्या 1312/2012/जोधपुर मैसर्स कविता फ़ैन्सी स्टोर, घण्टाघर, जोधपुर बनाम उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर, जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 11.11.2013 का हवाला देते हुए व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रशासनिक अधिकारी को प्रशमन हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया।

7. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच में पायी गयी अनियमितता एवं स्वयं अपीलार्थी की स्वीकारोक्ति के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरणों में नियमानुसार कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है एवं अपीलार्थी की करापवंचन की मानसिकता/स्वीकारोक्ति को दृष्टिगत रखते हुए ही प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण प्रशमन योग्य नहीं मानते हुए अपीलार्थी के प्रशमन प्रार्थना-पत्र



अस्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावलियों का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया।

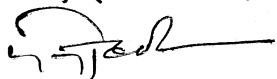
9. प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच में अपीलार्थी द्वारा 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल की बिक्री को कर मुक्त जॉब चार्ज अकाउण्ट में अंकित करते हुए कर चोरी किया जाना पाया गया। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया। उक्त आदेशों के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए, प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 68(1) के तहत प्रशमन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाकर, धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति की सीमा तक प्रकरणों को प्रशमित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

10. प्रशासनिक अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक अधिकारी ने पृथक-पृथक पारित किये गये अपीलाधीन आदेशों दिनांक 17.09.2014 से अपीलार्थी के प्रार्थना-पत्र, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अस्वीकार किये हैं। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के स्थापित सिद्धान्तों की अवहेलना में पारित किये जाने से विधिसम्मत नहीं कहे जा सकते हैं। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 के तहत भी व्यवहारी के विरुद्ध कोई आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करना आज्ञापक है। नियम 48 उद्धरित करना सुसंगत होगा :-

**48. Granting opportunity of hearing and recording of reasons,-**

Where an assessing authority or any other officer, enhances the admitted tax liability of a dealer, or imposes a penalty on him or on any other person under the provisions of the Act or the Rules, or passes any order detrimental to their interest, the said authority or officer shall record the reasons thereof, and no such order shall be passed unless the dealer or the person has been given a reasonable opportunity of being heard.

11. विधायिका ने वेट अधिनियम का प्रावधान 68 अनावश्यक रूप से न्यायिक प्रक्रिया में फंसने से बचाने हेतु प्रावधित किया गया है। धारा 68 की सुसंगत उपधाराएं इस प्रकार हैं :-




**68. Composition of offences. -**

- (1) Where a person or a dealer is charged under this Act with the offence of avoidance or evasion of tax in any manner and at any time; he may make an application in the prescribed form and manner to the Deputy Commissioner (Administration) having jurisdiction, admitting his offence and making request therein for composition of the offence in lieu of penalty or prosecution.
- (2) The Deputy Commissioner (Administration) may, whether or not an assessment order under any section of this Act has been passed, accept from the person who made the application under sub-section (1), by way of composition of the offence in lieu of penalty or prosecution a sum equal to of the amount of tax avoided or evaded.
- (3) .....
- (4) .....
- (5) .....
- (6) .....
- (7) Notwithstanding anything contained in section 82, no appeal shall lie or subsist against an order of composition made under this Act.

12. उपधारा (1) के तहत दायर प्रार्थना-पत्र को प्रशासनिक अधिकारी उपधारा (2) के तहत स्वीकार कर सकता है। इस प्रावधान में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के तहत व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने के अधिकार प्रदत्त हैं तथा 'may' शब्द उपयोग किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी ने प्रदत्त शक्ति का प्रयोग नहीं करते हुए अपीलाधीन आदेश में व्यवहारी के आवेदन को अस्वीकार किया है, लेकिन आदेश से पूर्व व्यवहारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना विधिक आवश्यकता है। अतः प्रशासनिक अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार की जाती हैं तथा प्रशासनिक अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आवेदनकर्ता व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त धारा 68 की भावना के मद्देनजर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

13. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की तीनों अपीलें स्वीकार करते हुए प्रकरण प्रशासनिक अधिकारी को उपरोक्तानुसार प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

14. निर्णय सुनाया गया।

  
 18.12.2014  
 ( मनोहर पुरी )  
 सदस्य